राजस्थान सार्वजनिक सेवा आयोग

बनाम

कैला कुमार पालीवाल और अन्य

2 मई, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.]

सेवा कानून-पदोन्नति-प्रधानाध्यापक के पद पर माध्यमिक विधालय-शिक्षक ग्रेड III की पात्रता शुरू में प्रयोगशाला सहायक के रूप में नियुक्त धारित ऐसे शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के हकदार नहीं है-उच्चतर पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए पद व्यक्ति के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए- स्पष्ट शक्ति के अभाव में चयन समिति द्वारा भी ऐसी योग्यता होनी चाहिए- स्पष्ट शक्ति के अभाव में चयन समिति द्वारा भी ऐसी योग्यता में छूट नहीं दी जा सकती है- योग्यता के मानदंडों का निर्धारण क्षेत्र में लागू नियमों पर निर्भर करेगा- राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 राजस्थान शिक्षा (अधीनस्थ सेवाएं) नियम, 1971 उत्तरदाताओं को शुरू में प्रयोगशाला सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने शिक्षक ग्रेड III के पद पर भी काम किया था। माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती के लिए उनके

मामलों पर अपीलार्थी-आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया था। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्देश देने की उनकी रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। अंतर-अदालत अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादियों की याचिका को स्वीकार कर लिया।

इस न्यायालय में की गई अपीलों में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या प्रयोगशाला सहायक और शिक्षक ग्रेड III के रूप में उत्तरदाताओं का अनुभव वे प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार थे।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1 . प्रधानाध्यापक के पद राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 द्वारा शासित होते हैं। पांच साल का शिक्षण अनुभव आवश्यक है, हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए विचार जो बदले में कुछ श्रेणियों या पदों पर कुछ क्षमता में शिक्षण के लिए संदर्भित है। इसलिए जो लोग प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक या माध्यमिक शिक्षा की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ शिक्षक ग्रेड III के पदों पर आसीन थे, वे 1970 के दोनों नियमों के दायरे और उद्देश्य को देखते हुए माध्यमिक कक्षाओं या उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के हकदार नहीं होंगे। राजस्थान शिक्षा (अधीनस्थ

सेवा) नियम, 1971 आयोग अपने विचार में सही था। [पारस 13,14 और 17] [1137-सी, डी, ई; 1138-ए-बी]

1.2. तत्काल मामले में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। न केवल हेडमास्टर के पद नियमों के एक अलग समूह द्वारा शासित होते हैं, पद शिक्षक ग्रेड III शिक्षक ग्रेड II के पदों के लिए एक पदोन्नति का अवसर प्रदान करता है जो बदले में शिक्षक के अन्य ग्रेडों में पदोन्नति का प्रावधान करता है। इस प्रकार यह अकल्पनीय है कि इस पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त अनुभव अधीनस्थ सेवा नियमों द्वारा शासित तृतीय श्रेणी के शिक्षक हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे, हालांकि विशेष कक्षाओं में शिक्षण का अनुभव इसके लिए प्रासंगिक है। [पारस 26 और 27] [1140-एफ, जी]

ए. उमरानी बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य। [2004] 7 एससीसी 112, पर निर्भर।

राजस्थान राज्य बनाम मनमोहन सिंह और अन्य। [2003] 1 सीडीआर 839, अस्वीकृत।

2.1. उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाने वाले व्यक्ति की आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसके लिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि चयन समिति

भी किसी भी व्यक्त शक्ति की अनुपस्थिति में इसे प्रदत्त शक्ति ऐसी आवश्यक योग्यता में ढील नहीं दे सकती है। [पैरा 20] [1138-डी]

जे. सी. यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। [1990] 2 एस.सी.सी 189 और डॉ. भानु प्रसाद पांडा बनाम कुलाधिपति, संबलपुर विश्वविद्यालय और अन्य। [2001] 8 एस.सी.सी. 532, संदर्भित।

2.2. किसी पद पर भर्ती नियमों के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए। मैदान में काम करना। आवश्यक योग्यता किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अधिसूचना जारी करने की तारीख या नियमों में निर्दिष्ट के रूप में और केवल उसके अभाव में आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक योग्यता प्रासंगिक तिथि होगी। [पैरा 21] [1138-ई, एफ]

अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम चंदर शेखर और अन्य [1997] 4 एससीसी 18; यू.पी. लोक सेवा आयोग यू.पी. इलाहाबाद और अन्य बनाम अल्पना [1994] 2 एस.सी.सी. 723 और हरपाल कौर चहल बनाम निदेशक, पंजाब निर्देश, पंजाब और अन्य। [1995] सप.4 एस.सी.सी. 706, संदर्भित।

2.3. यहां तक कि जहां छूट का प्रावधान है, उदाहरण के लिए राजस्थान सार्वजनिक सेवा आयोग, आयु में छूट इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। [पैरा 22] [1138-जी]

केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम सजल कुमार रॉय और अन्य, [2006] 8 एस.सी.सी. 671 और पी.के. कामचंद्र लायर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। [1984] 2 एस.सी.सी. 141, संदर्भित।

2.4. सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति शिक्षण के मानदंडों को पूरा करता है नियम स्पष्ट हैं, उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। केवल जहां नियम स्पष्ट नहीं हैं, संबंधित उम्मीदवार को पर्याप्त जगह रखनी चाहिए। यह दिखाने के लिए सामग्री कि वह अपेक्षित योग्यता को पूरा करता है। [पैरा 23] [1138-एच; 1139-ए]

बिहार राज्य और अन्य बनाम आसिस कुमार मुखर्जी और अन्य आदि। ए.आई.आर.(1975) एस.सी.192, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की सिविल अपील सं. 2317

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) सं. 785 2003 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7031 में 2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.09.2005 से।

के साथ

2007 का सिविल अपील संख्या 2318

मनीष कुमार, अंसार अहमद चौधरी, मधुरिमा तातिया और अपीलार्थी की ओर से अरुणेश्वर गुप्ता।

प्रत्यर्थीयों के लिए बी.डी. शर्मा और विक्रम जीत सिकंद।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यहाँ प्रत्यर्थी सरकार में उच्च विद्यालय प्रयोगशाला सहायक थे। उन्हें उक्त पदों पर 24.1.1992 पर या उसके आसपास नियुक्त किया गया था। उन्होंने 13.10.1997 से शिक्षक ग्रेड-III के पद पर काम किया।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "आयोग") माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों के लिए 7.3.2002 पर या उसके बारे में एक विज्ञापन जारी किया। राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 के संदर्भ में इसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता और अन्य शर्तें इस प्रकार हैंः

क्रम संख्या	पदनाम	प्रतिशत सहित भर्ती की विधि	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	पदोन्नति वाला पद	पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव	अधिकतम आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानाध्यापक सी.सै.स्कुल (लड़कों के लिए)	50% सीधी भर्ती व 50% पदोन्नति से	1(क) शिक्षा में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा (ख)हाई/जूनियर को	संलग्न अनुसूची के खंड सी,डी,ई और एफ में	1(क) शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री	33 वर्ष

			पढ़ाने का पांच साल का अनुभव, मिडिल स्कुलों के प्रशासनिक प्रभार का चार साल का अनुभव, हाई सी.सै./सी.सै. को पढ़ाने का तीन साल का अनुभव या शिक्षक ग्रेड द्वितीय के पद पर पांच साल का अनुभव अथवा उपरोक्त राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 से जुड़ी अनुसूची की धारा सी,डी,ई और एफ में से किसी के तहत नोटः 1. उपर उल्लिखित डिग्री या डिप्लोमा भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविधालय य सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी	ग्रेड द्वितीय में शिक्षक	(ख) हाई/जूनियर को पढ़ाने का पांच साल का अनुभव या मिडल स्कुल में प्रशासनिक प्रभार का चार साल का अनुभव या हाई /जूनि .हायर.सै./हायर सै. में पढ़ाने का तीन साल का अनुभव अथवा योग्यताएं का ॅलम 4 के 1(क) में निर्धारित हैं और उन्हें सेक्रेटरी बोर्ड द्वारा छूट दी जानी चाहिए। उपनियम(1) में निर्धारित योग्यता रखने से शिक्षा, राजस्थान 1(ख) वर्षो की	

			विश्वविधालय का होगा। 2. आरटीएस / बीएसटीसी / स्कूलों में पढ़ाना हाई/जूनियर में पढ़ाने के बराबर माना जाएगा।		संख्या के संबंध में	

4. अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि उत्तरदाताओं ने पूरा नहीं किया उक्त नियमों में निहित अपेक्षित पात्रता मानदंड, माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए उनके मामलों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया था।

5. निर्विवाद रूप से उक्त नियमों के संदर्भ में, प्रमुख के पद का 50 प्रतिशत मास्टर को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था, जबकि शेष 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

6. उत्तरदाताओं ने एक रिट याचिका दायर कर अन्य बातों के साथ-साथ एक याचिका जारी करने का अनुरोध किया आयोग को उक्त पदों पर उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्देश देने वाला या अनिवार्य लिखित आदेश उपरोक्त विज्ञापन दिनांक 7.3.2002 को ध्यान में रखते हुए प्रयोगशाला सहायक के रूप में अनुभव। उच्च न्यायालय का एक विद्वान एकल न्यायाधीश एक निर्णय और आदेश

दिनांक 17.12.2003 द्वारा उक्त न्यायालय की एक समन्वय पीठ के पहले के निर्णय पर या उसके आधार पर। श्रीमती मंजुलता वी. आरपीएससी और ए.एन.आर., 24.1.1997 पर निपटाया गया एस बी सी डब्लू पी नंबर 421/1997 ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ अदालत के भीतर अपीलों को फिर से प्राथमिकता दी गई और विवादित फैसले के कारण, राजस्थान राज्य बनाम वी. मनोहर सिंह और अन्य में दिए गए एक अन्य खंड पीठ के फैसले के बाद खंड पीठ (2003) सी.डी.आर. 839 ने इसकी अनुमति दी।

7. राजस्थान राज्य और राजस्थान लोक सेवा आयोग हैं - इस प्रकार, हमारे सामने।

8. एकमात्र प्रश्न जो इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होता है यह इस बारे में है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मत सही था कि प्रयोगशाला सहायक या शिक्षक ग्रेड-III के रूप में काम करते हुए उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त अनुभव उक्त विज्ञापन दिनांक 7.3.2002 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है।

9. राज्य के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाएँ राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 और राजस्थान शिक्षा (अधीनस्थ सेवा) नियम, 1971 द्वारा शासित है। अधीनस्थ सेवा में वे पद शामिल हैं जो उसमें संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। एक शिक्षक ग्रेड-III के साथ-साथ

एक प्रयोगशाला सहायक भी 'अधीनस्थ सेवा' शब्द के दायरे में आता है। एक पद धारण करने के लिए न्यूनतम योग्यता शिक्षक ग्रेड-III प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक है, जबकि प्रयोगशाला सहायक एक वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान के साथ माध्यमिक है।

10. दूसरी ओर राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 1970, हेड मास्टर्स, सहायक हेड मास्टर्स, राजस्थान सार्वजनिक सेवा आयोग की नियुक्ति के साथ व्यवहार करें। विद्यालयों के उप निरीक्षक आदि, न्यूनतम योग्यता जिसके लिए शिक्षा में स्नातक की डिग्री और डिग्री या डिप्लोमा हैं।

11. राजस्थान शिक्षा (अधीनस्थ सेवा) नियम, 1971 में शिक्षक ग्रेड-II के पद मौजूद हैं। मूक-बधिर, नेत्रहीन विद्यालयों में शिक्षक ग्रेड-III प्रयोगशाला सहायक और शिक्षकों के पद अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक ग्रेड-II उप-निरीक्षक और प्रवर्तन सहायक आदि के पद पर पदोन्नति।

12. उक्त पदों में वरिष्ठ पदों के लिए मार्ग भी उपलब्ध है। शिक्षक जिन्हें दिनांक 6.1.1990 की अधिसूचना द्वारा शिक्षक ग्रेड-II के लिए प्रतिस्थापित किया गया था। निर्विवाद रूप से कुछ अन्य पद हैं जो पदोन्नति के साथ-साथ शिक्षक ग्रेड-II की श्रेणी से भरे जाते हैं, उदाहरण के लिए व्याख्याता आदि शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो में तकनीकी परीक्षण सहायक आदि।

13. हेडमास्टर के पद, जिन्हें राज्य में दोहराया जाएगा, शासित होते हैं 1970 के नियमों के अनुसार। हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पांच साल का शिक्षण अनुभव आवश्यक है जो बदले में संदर्भित है कुछ श्रेणियों या पदों पर कुछ क्षमता में शिक्षण।

14. इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि जो धारण कर रहे थे मैट्रिक या माध्यमिक शिक्षा की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के साथ प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र के साथ शिक्षक ग्रेड-III के पद माध्यमिक कक्षाओं या उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के हकदार होंगे।

15. मंजुलता (ऊपर) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने भरोसा व्यक्त किया;

> "इसलिए प्रत्यर्थी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था आर.पी.एस.सी., जिसने उपस्थिति में इस न्यायालय को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता वह इस पद के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है क्योंकि वह प्रयोगशाला के रूप में काम कर रही है। सहायक, जो नियमित शिक्षकों के पद से कम का पद है और प्रयोगशाला के रूप में उनका अनुभव। सहायक उसे शिक्षण अनुभव की ओर से कोई श्रेय नहीं देता है। श्री कुमावत आरपीएससी की ओर से भी सूचित किया कि इस प्रश्न का पता एक निकाय से लगाया गया था आरपीएससी द्वारा विशेषज्ञ

जिसमें समिति ने अपनी राय दी है नकारात्मक में और इसलिए, कोई प्रयोगशाला नहीं। सहायक योग्य माने जाते हैं। मुखिया के पद के लिए-मालकिन/मुखिया"।

16. अतः यह स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग विशेषज्ञ निकाय अन्य विशेषज्ञों से राय प्राप्त करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माध्यमिक [2007] के प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से 5 एस.सी.आर. स्कूल, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से, शिक्षक ग्रेड-III के पद के रूप में एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता पर्याप्त नहीं है।

17. हम 1970 के दोनों नियमों के दायरे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1971 के नियमों में भी यह राय है कि आयोग अपने निर्णय में सही था।

18. मनोहर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ सिंह (उपरोक्त) ग्रेड-III शिक्षक के अनुभव को ग्रेड-II शिक्षक के अनुभव के साथ जोड़ने के मामले पर विचार कर रहे थे। यह इस आधार पर आगे बढ़ा कि एक बार एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई थी, ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ग्रेड-II और ग्रेड-II दोनों के रूप में अलग-अलग शिक्षण अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेड-III शिक्षक।

19. विद्वान न्यायाधीश सम्मान के साथ, इस तरह का निर्णय लेने में सही नहीं थे देखें।

20. उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाने वाला व्यक्ति आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे माना नहीं जा सकता है। यहां तक कि चयन समिति को किसी भी स्पष्ट शक्ति के अभाव में इस तरह की आवश्यक योग्यता में ढील नहीं दी जा सकती है। जे.सी. देखें। यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। [1990] 2 एस. सी. सी. 189 और डॉ. भानु प्रसाद पांडा बनाम कुलाधिपति, संबलपुर विश्वविद्यालय और अन्य। [2001] 8 एससीसी 532

21. किसी पद पर भर्ती नियमों के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए। मैदान में काम करना। अधिसूचना जारी करने की तारीख या नियमों में निर्दिष्ट के रूप में एक व्यक्ति के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए और केवल उसके अभाव में आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त योग्यता प्रासंगिक तिथि होगी। अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम वी. चंदर शेखर और अन्य [1997] 4 एस.सी.सी. 18 यू.पी. लोक सेवा आयोग यू.पी. इलाहाबाद और ए.एन.आर. बनाम अल्पना, [1994] 2 एस.सी.सी. 723 और हरपाल कौर चहल बनाम निदेशक, पंजाब निर्देश, पंजाब और अन्य। [1995] पूरक 4 एस.सी.सी. 706

22. यहां तक कि जहां छूट का प्रावधान है, उदाहरण के लिए आयु में छूट, इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। (केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम सजल कुमार रॉय और अन्य। [2006] 8

एस.सी.सी. 671 और पी.के. रामचंद्र अय्यर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। [1984] 2 एस.सी.सी. 141)

23. हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति जो शिक्षण अनुभव के मानदंडों को पूरा करता है या नहीं करता है, वह राजस्थान सार्वजनिक सेवा आयोग पर निर्भर करेगा। क्षेत्र में काम करने वाले नियम। जब नियम स्पष्ट और स्पष्ट होते हैं, तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए। केवल ऐसे मामले में जहां नियम स्पष्ट नहीं हैं, संबंधित उम्मीदवार को यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री रखनी चाहिए कि वह अपेक्षित योग्यता को पूरा करता है। (बिहार राज्य और अन्य बनाम आसिस कुमार मुखर्जी और ओआरएस। आदि। ए.आई.आर. (1975) एस. सी. 192

24. हम देख सकते हैं कि पी. के. रामचंद्र अयर में यह न्यायालय आयोजित;

> "31. इस संदर्भ में एक और निवेदन का निपटारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समिति में विशेषज्ञ शामिल थे और वे अत्यधिक थे योग्य व्यक्ति जो मूल्यांकन और मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे उसके और न्यायालय के समक्ष प्रत्येक उम्मीदवार के सापेक्ष गुण हैं ऐसा करने के लिए कम से कम सक्षम और इसलिए इसे प्रतिस्थापित करना बुद्धिमानी नहीं होगी। न्यायालय

के निर्णय द्वारा विशेषज्ञों का निर्णय। इस संबंध में निर्भरता थी डॉ. एम.सी.गुप्ता बनाम डॉ. अरुण कुमार गुप्ता, जिसमें यह न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

जब चयन आयोग द्वारा सहायता और सलाह के साथ किया जाता है तकनीकी अनुभव और उच्च शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण/अनुसंधान की जांच करने वाले विशेषज्ञ क्षेत्र में योग्यताएँ विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त राय में हस्तक्षेप करें जब तक कि उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए जाते हैं। यह आम तौर पर होगा न्यायालयों के लिए विवेकपूर्ण और सुरक्षित है कि वे शिक्षाविदों के निर्णय को छोड़ दें उन विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण है जो समस्याओं से अधिक परिचित हैं आम तौर पर अदालतों की तुलना में चेहरा हो सकता है। निस्संदेह यहाँ तक कि निकाय यदि वह बाध्यकारी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है चयन करने और चयनकर्ताओं की सिफारिश करने में नियुक्ति के लिए, असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय कानून के शासन को लागू करने के लिए अनुच्छेद के तहत एक रिट याचिका में हस्तक्षेप कर सकता है 226 ......

यह आग्रह किया गया कि एक बार यह स्वीकार कर लिया जाए कि चयन की शक्ति के रूप में और नियुक्ति आई. सी. ए. आर. में निहित है, न्यायालय को इसे हड़पना नहीं चाहिए शक्ति केवल इसलिए कि इसने एक अलग व्यक्ति को चुना होगा बेहतर योग्यता (बिहार राज्य बनाम डॉ. असिस कुमार मुखर्जी)। संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा कर्तव्यों का, जैसा कि डॉ.एम.सी. गुप्ता मामला। हालाँकि, एक समाज को स्थापित करने का कार्य कानून का शासन इस न्यायालय को सौंपा गया है और यह इसका त्याग नहीं कर सकता है। कार्य। एक बार जब यह सबसे संतोषजनक रूप से स्थापित हो जाता है कि चयन 6 द्वारा निर्धारित स्थापित मानदंडों का उल्लंघन था विज्ञापन और चयन समिति की शक्ति और प्रक्रिया सार्वजनिक रोजगार के मामले में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चयन और समानता और परिणामी अन्याय को सुधारना और संवैधानिक मूल्य स्थापित करना। इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रत्यर्थी 6 का चयन इसके विपरीत है नियम और आदेश और योग्यता के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन। चयन के समय वे इस पद के लिए अयोग्य थे। उनका चयन और नियुक्ति को रद्द करके अलग रखने की आवश्यकता होगी।"

25. ए. उमरानी बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य [2004] 7 एस.सी.सी. 112, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया;

"हमारी सुविचारित राय में नियमितीकरण ऐसा नहीं है और न ही हो सकता है। अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर किसी भी "राज्य" द्वारा भर्ती का तरीका भारत के संविधान या किसी निकाय या प्राधिकरण द्वारा शासित वैधानिक अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम। यह भी अब ठीक है तय किया कि अनिवार्य का उल्लंघन करते हुए की गई नियुक्ति कानून के प्रावधानों और विशेष रूप से, न्यूनतम की अनदेखी पूरी तरह से अवैध। इस तरह की अवैधता को सहारा लेने से ठीक नहीं किया जा सकता है नियमितीकरण। (एच.पी. बनाम सुरेश कुमार वर्मा)"

26. तत्काल मामले में, नियम बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट हैं।

27. तत्काल मामले में न केवल हेडमास्टर के पदों को नियंत्रित किया जाता है नियमों के एक अलग समूह द्वारा, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, कि पद शिक्षक ग्रेड-III शिक्षक ग्रेड-II के पदों के लिए पदोन्नति का अवसर प्रदान करता है जो बदले में शिक्षक के अन्य ग्रेडों में पदोन्नति प्रदान करता है। इस प्रकार हमारी राय में यह अकल्पनीय है कि अधीनस्थ सेवा नियमों द्वारा शासित शिक्षक ग्रेड-III के पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त अनुभव हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार

किए जाने का हकदार होगा, हालांकि विशेष कक्षाओं में शिक्षण का अनुभव इसके लिए प्रासंगिक है।

28. उपरोक्त कारणों से विवादित निर्णय डिवीजन बेंच को बनाए नहीं रखा जा सकता है जिसे तदनुसार अलग रखा जाता है। अपीलों की अनुमति है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भाविका कुलहरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।